तैयारी औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपी गई जिम्मेदारी

उद्यमियों को राहत, औद्योगिक जमीन की कीमत तर्कसंगत होगी

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। राज्य सरकार ने उद्योग लगाने की बड़ी अड़चन बन चुकी महंगी औद्योगिक जमीन पर ठोस नियंत्रण की तैयारी तेज कर दी है। निवेश को आसान और सस्ता बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक जमीन की दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय किया गया है जिससे उद्योगों की लागत को घटाया जा सके।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जमीन और आधारभूत ढांचे की लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसी वजह से औद्योगिक जमीन की कीमतों को नियंत्रित करने का फैसला किया गया है। यह उद्यमियों के लिए बड़ी राहत है।

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति को औद्योगिक जमीन की कीमत तय करने की प्रक्रिया की समीक्षा और उसे निवेशकों के अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति जमीन अधिग्रहण, विकास कार्य और बुनियादी सुविधाओं पर आने वाले खर्च का दोबारा मूल्यांकन कर रही है। साथ ही उद्योगों को तुरंत काम शुरू करने में मदद देने के लिए तैयार औद्योगिक शेड योजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत निजी सहभागिता से उद्योगों को पहले से बने कारखाने किराये पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इससे उद्योगपतियों पर शुरुआती खर्च का बोझ कम होगा और छोटे व मझोले उद्योग तेजी से उत्पादन शुरू कर सकेंगे।

औद्योगिक जमीन की कीमत तय करने में पारदर्शिता लाने के लिए मानक लागत दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इन निर्देशों के लागू होने से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की दर तय करने का एक समान तरीका होगा। इससे मनमानी कीमतों पर रोक लगेगी। समिति इन निर्देशों को अंतिम रूप दे रही है जिन्हें बाद में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू किया जाएगा।जमीन की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रण में लाने की रणनीति भी अपनाई जा रही है।

औद्योगिक जमीन के लिए बनी विशेष समिति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लंबे समय से खाली पड़ी और अधिग्रहण से बाहर औद्योगिक जमीन को उपयोग में लाने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। इस समिति ने करीब 3.6 लाख हेक्टेयर यानी लगभग 9 लाख एकड़ जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए खोलने की सिफारिशें तैयार कर ली हैं। साथ ही, नुकसान में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों की बेकार पड़ी जमीन और ग्राम समाज की जमीन को भी औद्योगिक उपयोग में लाने की तैयारी है।